प्रिस्क्रिप्शन या कॉल-सेंटर की अंग्रेज़ीः भाषाई राष्ट्रवाद से आगे बढ़ने की ज़रूरत

Prescription or Call-center English: The Need to Move Beyond Linguistic Jingoism

चिंकी सिन्हा

Chinki Sinha
March 12, 2012

जब गौरव दलाल से यह पूछा गया कि वह अपने खाली समय में क्या करना चाहेगा तो उसने तपाक से कहा, ‘‘इसे ज़रा दुबारा कहिए ’’. उसे इसका जवाब मालूम था और वह यह अच्छी तरह से जानता भी था, लेकिन यह सवाल उसे जाना-पहचाना नहीं लगता था, क्योंकि आठवें दर्जे का छात्र अपनी हॉबी के बारे में कुछ खास तरह के सवालों का जवाब देने के लिए ही अभ्यस्त होता है. हरियाणा के एसआर मेमोरियल प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के बोर्ड पर यह ‘मोटो’ लगा हुआ है, ‘‘शिक्षाशास्त्र कोई व्यवसाय नहीं, मिशन है’’. इसे दूसरी मंज़िल की कक्षा के अन्य छात्र भी ऐसे ही दोहराते हैं. कोई भी अंग्रेज़ी के भ्रामक शब्दों में पूछे गए इन सवालों का आगे बढ़कर जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें आड़े-तिरछे शब्दों में पूछे गए सवालों का जवाब देना सिखाया ही नहीं जाता.

अंग्रेज़ी की स्थिति से संबंधित 2009 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्कूलों के पहले दर्जे के 56 प्रतिशत बच्चे अंग्रेज़ी के कैपिटल लैटर भी नहीं पढ़ पाते. सन् 2005 में पहली बार जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठन ‘‘प्रथम’’ द्वारा बच्चों के अंग्रेज़ी के स्तर को मापने का प्रयास किया गया था. इन परिणामों से भाषा शिक्षण की स्थिति का अंदाज़ा लग जाता है.

राज्य सरकारें या तो अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोल रही हैं या फिर अंग्रेज़ी भाषा के शिक्षण की लोकप्रिय माँग को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ी की पढ़ाई शुरू कर रही हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी को आज बेहतर जीवन का पासपोर्ट माना जाता है. दिल्ली विश्वविद्यालय में बैचलर डिग्री की पढ़ाई करने वाली गौरव की शिक्षिका ने जब स्कूल के निर्देशक द्वारा पूछे गए सवाल के बाद स्वयं दखल देते हुए गौरव से अपनी हॉबी गिनाने के लिए कहा तब जाकर गौरव ने जवाब दिया, ‘‘पढ़ना, लिखना, खेलकूद और संगीत’’.

अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण पर चलने वाली बहस का मूल मुद्दा यही है कि अंग्रेज़ी के अध्यापकों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ऐसे छात्रों को, जिनके घरों में अंग्रेज़ी बोली नहीं जाती, भाषा सिखाने का बुनियादी ज्ञान भी नहीं है. इस काम को अंजाम देने के लिए सरकार या प्राइवेट स्कूलों की अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोलने की मात्र इच्छा ही काफ़ी नहीं है. इसके लिए और भी बहुत कुछ करना होगा.

अंग्रेज़ी भाषा के शिक्षण की माँग में हुई बढ़ोतरी के बावजूद, जिसके कारण पश्चिम बंगाल की सरकार को भाषा शिक्षण की नीति की पुनरीक्षा करने के लिए बाध्य होना पड़ा, अंग्रेज़ी भाषा के शिक्षण के

संदर्भ में वांछित परिणाम नहीं मिल पाए हैं. पटना (बिहार) में तो प्रशासन ने अपने स्कूलों को छठे दर्जे तक शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग करने और प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेज़ी की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए बाध्य कर दिया है. हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्कूलों में घटते दाखिले पर लंबी चर्चा के बाद अपने विद्या और शिशु विद्यालयों में अंग्रेज़ी माध्यम के खंड जोड़ने का निर्णय किया है. गाँवों में, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और यहाँ तक कि शहरों में भी कितने ही गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल आसानी से दिख जाएँगे.ये स्कूल सिर्फ एक कमरे के अपार्टमेंट में चलाए जाते हैं और इनमें अलग-अलग दर्जे के मिले-जुले छात्रों की सामूहिक कक्षाएँ चलाई जाती हैं. आम तौर पर माँ-बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में इस विश्वास के आधार पर भर्ती कराते हैं कि अंग्रेज़ी की पढ़ाई से बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा. परंतु जिस तरह से अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, उससे दोनों ही प्रकार के स्कूलों में ये संभावनाएँ चौपट हो जाती हैं.

उत्तर प्रदेश, बिहार और खास तौर पर बंगाल की राज्य सरकारों ने बहुत लंबे समय तक सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी की पढ़ाई नहीं होने दी. उनकी धारणा थी कि अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद की विरासत है और इसे बंद कर देना चाहिए. आज अंग्रेज़ी की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी गई है,लेकिन नई दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल और मिशनरी स्कूलों को छोड़कर जो शिक्षकों के शिक्षण का खर्च उठा सकते हैं, देश-भर के अधिकांश स्कूल मात्र अंग्रेज़ी की बढ़ती माँग को पूरा करने का प्रयास रहे हैं और शिक्षण का यह कार्य उन शिक्षकों के भरोसे जारी रखा जा रहा है जो स्वयं भी अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं रखते.

कई मामलों में तो अंग्रेज़ी मात्र हिंदी शब्दों का अनुवाद करके ही सिखाई जाती है. इस तरीके से छात्रों को सिखाए जाने वाले शब्दों और उच्चारण से आगे जाकर वे इस भाषा में सहज नहीं हो सकते. अकेले बिहार में ही पाँचवें दर्जे के केवल 33 प्रतिशत बच्चे ही अंग्रेज़ी में सरल वाक्य पढ़ सकते हैं. असम, छत्तीसगढ़,गुजरात, झारखंड,कर्नाटक,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिसा जैसे अन्य राज्यों में यह प्रतिशत 7 और 31 प्रतिशत के बीच में है.

तीन दशक पहले समाजवादी राजनैतिक नेता राममनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर समाजवादी नेताओं ने शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी और स्थानीय भाषाओं को स्थापित कर दिया था. लोहिया जी के अनुसार अंग्रेज़ी को जानने वालों का संख्या नगण्य है और इसका उपयोग दमन के एक साधन के रूप में किया जाता है. वे अंग्रेज़ी भाषा को विषमता फैलाने का एक साधन मानते थे, जिसके कारण बुद्धिजीवियों और आम आदमी के बीच खाई बढ़ती जा रही थी और वे मानते थे कि शासक वर्ग में उच्च वर्ग, समृद्ध लोग और अंग्रेज़ीभाषी लोग ही शामिल थे.

सन् 1981 में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेज़ी या हिंदी के स्थान पर बंगला पढ़ाना शुरू कर दिया गया. सन् 1984 में प्राथमिक स्कूलों से अंग्रेज़ी की पढ़ाई खत्म कर दी गई. परंतु, सन् 2010 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने अंग्रेज़ी शिक्षा के बारे में अपनी नीति पूरी तरह बदल डाली और सरकारी स्कूलों में माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर अंग्रेज़ी माध्यम की कक्षाएँ शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए. लेकिन भाषा शिक्षण की चुनौती उस स्तर पर भी बनी रही.

अंग्रेज़ी को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग द्वारा उपयोगी भाषा माना जाता है और यही एकमात्र ज़रिया है जिससे वे अपने-आपको समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं. सन् 2010 में उत्तर प्रदेश के एक गरीब गाँव में अंग्रेज़ी की देवी का मंदिर बनना शुरू हुआ, जिसकी तुलना स्टैचू ऑफ़ लिबर्टी से की जा सकती है. मनु जोज़ेफ़, संपादक, ओपन मैगेज़ीन ने लिखा है कि हज़ारों गाँव वालों ने, जिनमें से अधिकांश दलित थे, इसकी ज़मीन तैयार की थी. जोज़ेफ़ ने लिखा है कि "यह मंदिर देश के संभ्रांत लोगों के खिलाफ़ विद्रोह का प्रतीक है और दलित युवाओं के लिए एक संदेश हैः अंग्रेज़ी ही आपको बचा सकती है".

स्पैक्ट्रम के दूसरे छोर पर हिंदू राष्ट्रवादियों के संगठन संघ परिवार ने स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी को अपना लिया है और विभिन्न शहरों और कस्बों में शिविर आयोजित करके शिक्षकों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है. कोसी कलाँ के विद्या मंदिर स्कूल में आरएसएस के अधिकारियों ने प्रत्येक दर्जे में अंग्रेज़ी माध्यम का एक-एक खंड जोड़ दिया है. शुरू-शुरू में उन्होंने इसका विरोध किया,लेकिन माता-पिताओं की बढ़ती माँग के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाने के लिए अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता आवश्यक है. रेणु , जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन 'प्रथम' के साथ काम करती हैं, का मानना है कि भारत में अंग्रेज़ी की पढ़ाई रटंत विद्या की तरह की जाती है. "देशी उच्चारण,स्थानीय ज्ञान और विश्लेषणात्मक तरीके से और कक्षाओं में समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले संवादों" के माध्यम से इसकी पढ़ाई की जाती है.

अंग्रेज़ी माध्यम के देसी स्कूलों की समस्या है,अशिक्षित अध्यापक और कक्षाओं में शिक्षण- समग्री का अभाव. पाठ्यक्रम में यही ऐसा विषय होता है जिसके बारे में अध्यापकों को सबसे कम जानकारी होती है. इसके अलावा, अंग्रेज़ी ऐसा विषय भी नहीं है, जिसका उपयोग बच्चे कक्षा के बाहर कर सकें. कक्षा में अंग्रेज़ी सीखने का मानदंड बस यही है कि विद्यार्थी को जितना सिखाया जाता है, वह बस उतना ही दोहरा सके. रेणु ने यह भी कहा है कि "जो निष्कर्ष सामने आए हैं, उनके अनुसार ये बच्चे मात्र कृत्रिम वाक्यविन्यास और औपचारिक तौर-तरीके सीखते हैं, जिनका विचार-प्रक्रिया और जीवंत भाषा से कोई सरोकार नहीं होता."

चिंकी सिन्हा नई दिल्ली में एक पत्रकार हैं. वह 'कैसी ' विंटर 2012 में विज़िटिंग फ़ैलो हैं.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार <malhotravk@hotmail.com>